16. 38 hrs.

Title: Discussion on the Demands for Supplementary Grants (General) for 2001-2002.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up the next item − Item No.12 regarding Supplementary Demands for Grants − for discussion and voting.

Motion moved:

> "That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India, of certain further sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2002, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof, against Demand Nos. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 20, 21, 22, 25, 34, 36, 45, 48, 50, 51, 52, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 69, 70, 73, 76, 78, 80, 81, 83, 84,"

Shri Narayan Datt Tiwari to speak.

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल) : उपाध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 115 (1)(अ) के आधार पर प्रस्तुत जो अनुपूरक अनुदानों की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, मैं उनका रचनात्मक विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसके पहले कि मैं वर्तमान अनुपूरक प्रस्तावों पर कुछ कहूं,

मैं चिंता व्यक्त करना चाहता हूं कि जिस मूल बजट के अनुपूरक रूप में आज के पूरक प्रस्ताव वित्त मंत्री जी ने विचारार्थ पेश किए हैं, दुर्भाग्य से उस बजट पर हम सदन में गहराई से विचार नहीं कर सके। वित्त मंत्री जी के भााण से जो एक उत्साह का वातावरण बना था, वह बाद में स्टाक मार्केट में हुई घटनाओं,यू.टी.आई.व यूएस-64 की घटना और तहलका में हुई घटनाओं के कारण तिरोहित हो गया, अंतर्ध्यान हो गया। आज हम अनुपूरक बजट पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे इसमें एक विशेा प्र ाश्न उठाना है कि जो हमारी बजटीय प्रक्रियाएं व व्यवस्थाएं हैं, ग्लोबलाइजेशन का वातावरण है, उसके अनुरूप क्या वे पर्याप्त हैं ?

16.41 hrs. (डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय पीठासीन हुए)

क्या बजटीय मैनुअल में, बजट पेश करने में, चाहे पूरक बजट हो या मुख्य बजट हो, क्या नई जरूरतें तो पैदा नहीं हुई हैं ? मेरे पास रिजर्व बैंक आफ इंडिया की ओर से जारी एक बुलेटिन है, जिसमें कुछ बुनियादी सवालों का उल्लेख किया गया है कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हमारे संसाधनों पर, बजट पर और सारी प्रणाली पर हुआ है। किस तरह आज जो गरीबी और बेरोजगारी के प्रश्न हैं, उनकी इस बजटीय स्थिति में मदद नहीं हो पाती। यह बुलेटिन रिजर्व बैंक आफ इंडिया का है जिससे उसके डिप्टी गवर्नर श्री रेड्डी ने एक लेख लिखा है, वे गवर्नर के बाद सबसे ज्यादा काम करने वाले डिप्टी गर्वनर है। Resource-transferred to the rich is described as `incentive', while income-transferred to the poor is described as 'subsidy' − commonly perceived to be a derogatory term. Pro-poor-oriented growth is thus possible when intellectual community and policy-makers treat markets with suspicion that they deserve and the poor with the respect they they need. आज यह स्थिति हो गई है कि सब्सिडी का नाम लेना गुनाह हो गया है। हमारे सामने यह प्रश्न लगातार आता है कि कैसे सभी सब्सिडी कम हो या खत्म हो। सारे संसार में इस प्रश्न पर आज यह ि वचार दोबारा चल रहा है। विश्व अर्थशास्त्रियों का आकलन है कि जो वर्तमान दृटिकोण है, वह क्या बेरोजगारी और गरीबी के प्रति बदलना चाहिए। मेरे पास विश्व बैंक की दो नई पुस्तके है। जो विश्व बैंक की विश्व डवलपमेंट रिपोर्ट है, दूसरी जो ह्यूमन डवलपमेंट इंडैक्स रिपोर्ट है, उनमें उल्लेख है कि मानव प्रगति कितनी हुई है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पेयजल में और उन वियों में जिनसे हम मानव उन्नति की इंडैक्सिंग कर सकते है। इस मानव विकास की इंडैक्सिंग के प्रभाव से बजट पद्धति में परि वर्तन करने पर एक नए सिरे से विचार शुरू हो रहा है। हमारे बजट बनाने के तरीके के विाय में ही नए परिवर्तन की आवश्यकता है।

आज स्थिति यह है कि जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने अभी भारत सरकार की वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी की है:

> "Union finances have become less adequate, less autonomous and more vulnerable through the 1990s."

उन्होनें केवल वित्त मंत्री जी के काल का नहीं, पिछले दस सालों का भी विश्लेाण किया है:

> "Voted expenditure, as a percentage of total disbursement, has fallen from 44.51 per cent in 1992-93 to 31.94 per cent in 1997-98."

यानी इस लोक सभा में वोट के लिए जो अनुदान प्रस्तुत किये गये थे और जो चार्जड थे, जिन पर वोट नहीं होता, आज उसका प्रतिशत 44.51 प्रतिशत से घटकर 31.94 रह गया है।

It says further:

> "Therefore, there is less autonomy for applying available resources for current applications."

इससे जो आज संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, वे घटते जा रहे हैं।

It says again:

> "Repayment, as a percentage of borrowing, has increased from 72 per cent in 1991 to 86.74 per cent in 1999."

जो हम ब्याज देते हैं, कुल उधार पर उसकी धनराशि,उधार पर ली गई कुल धनराशि के ब्याज 72 फीसदी से बढ़कर आज 1999 में 86 प्रतिशत हो गयी है। It

indicates that only about 13 per cent of current borrowing is usable for current services. इससे क्या स्पट होता है कि जो इस समय उधार लिया जा रहा है, सरकार के द्वारा लाखों रुपये के हिसाब से जो उधार लिया जा रहा है, वह अभी पुराने कर्ज को अदा करने के लिए लिया जा रहा है और उस धनराशि का लगभग केवल तेरह प्रतिशत भाग आज नये विनियोजन के लिए उपलब्ध है, इंवेस्टमेंट के लिए है। आज यह स्थिति है। मैं उस सारी वस्तुकथा पर नहीं जाना चाहता जिसका उल्लेख आम बजट में किया गया है। शायद यह उपयुक्त अवसर भी नहीं है। मैं केवल संकेत के लिए कहना चाहूंगा कि कोई न कोई अवसर निकालना चाहिए जबकि अर्थ-व्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर, आज की हालत पर इस संसद में समय देकर, विस्तार से, सब मुद्दों पर विचार किया जा सके जिनको आज संसार में उठाया जा रहा है। आज जो नयी अर्थ-व्यवस्था कही जाती है, वह गरीब देश हैं, उनके लिए यह उपयुक्त है या नहीं है? वर्ल्ड बैंक का दृटिकोण बदल रहा है और हमें जो विश्व आर्थिक संस्थाएं हैं, उनमें भारत को अधिक मजबूती के साथ नेतृत्व देना पड़ेगा । डब्ल्यूटीओ से लेकर जितनी संस्थाएं हैं, वे अपना दृटिकोण बदलें नहीं तो गरीब देश और गरीब होते जाएंगे और गरीब देशों में भी क्षेत्रीय गरीबी और क्षेत्रीय असमानता बढ़ती जाएगी जिसका विराट उल्लेख मेरे पास तमाम रिपोर्टें रखी हैं उनमें है लेकिन मैं सदन का अधिक समय इस अवसर पर नहीं लेना चाहता, फिर किसी अवसर पर समय लूंगा। इससे यह स्पट होता है कि हमारे देश में अन्तरप्रदेशीय या अलग-अलग गरीबी के इंडेक्स में भी कितने उतार-चढ़ाव हैं। एक प्रदेश के मुकाबले में केवल 1/5 प्रति व्यक्ति आमदनी किसानों की, गरीबों की है। मैं उन प्रदेशों का नाम नहीं लेना चाहता जो आज तुलना में अधिक आगे है । आज हमारा कुल कर्ज बढ़कर 9 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इसमें एक लाख 86 हजार करोड़ रुपये विदेशी कर्ज है और 7 लाख 14 करोड़ रुपये आन्तरिक, देश के अंदर का कर्ज है और इस कर्ज पर जो ब्याज देना पड़ता है, जैसा मैने पहले कहा, वह बढ़ता चला जा रहा है।

इस वर्ा एक विशेा बात हुई है। अल्प बचत योजनाओं की धनराशि कन्सालिडेटड फण्ड आफ इंडिया का हिस्सा बन गई हैं। हमारी समेकित निधि का हिस्सा बन गई है, जबकि संविधान के अनुसार वह पब्लिक एकाउन्टस का हिस्सा होनी चाहिए थी। संविधान में कहा गया है, कि जो सरकार की अपनी आमदनी नहीं है, ऐसी दूसरी आमदनी पब्लिक एकाउन्ट्स में जमा होनी चाहिए। लगभग एक लाख 80 हजार रुपए स्माल सेविग्स में जमा है, लेकिन इसको एक फण्ड में तबदील कर दिया गया है। यह सिक्योरिटी के रूप में जो आमदनी है, सरकार उसमें से बोरो कर लेती है, उधार ले लेती है। यह ठीक है कि नेशनल सेविंग से सरकार को 20 परसेंट मिलता है। इसका सिक्योरिटाइजेशन होता है, तो समझ में आता है। इस बारे में केन्द्रीय आडिट रिपोर्ट में भी कहा गया है -

> "The Consolidated Fund of India, which until 1998-99 used to end with deficit, emerged with a surplus of Rs. 1,51,000 crore at the end of 1999 and the Public Account, which used to remain in surplus, ended with a deficit of Rs. 1,52,000 crore. It occurred because beginning 1999, the Government had begun to formally borrow small savings from the National Savings Fund by issuing securities."

यह जो किया गया है, इसकी कोई सूचना पहले संसद को नही दी गई कि क्यों राट्रीय बजट के धन को पब्लिक एकाउन्ट्स से कन्सलिडेटड फण्ड आफ इंडिया में बदल दिया गया है। संविधान के आधार पर पूरा एक ढांचे का परिवर्तन हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ है? कन्सालिडेटड फण्ड आफ इंडिया में जो धनराशि है, उसके खर्च के हिसाब को आप देखें - 1997-98 में 51,162 करोड़ रुपए थी और यह 1998-99 में थोड़ी घटी, लेकिन फिर 2000-2001 में यह बढ़ कर 73,284 करोड़ रुपए हो गई। सप्लीमेंट्री बजट, प्रारम्भ से जब से प्रार्लियामेंट का निर्माण हुआ है, अंग्रेजों के जमाने से भी, यह कहा गया है और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी भी कहती रही है, सप्लीमेन्ट्री जो अनुपूरक है, मूल बजट में देखभाल करके ही प्राप्त करना चाहिए। ससंद में कई रिर्पोट्स पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की तरफ से पेश की जाती रही हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि उन रिपोट्र्स पर सदन में समयाभाव के कारण चर्चा नहीं होती है। लेकिन माननीय वित्त मंत्रीजी इस बात से सहमत होंगे, कि जो पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी हैं समय- समय पर वह लागू होनी चाहिये । आज प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, श्री वैंकटरमण जी और डा. जोशी आदि सभी की इस बारे में रिर्पोटस मेरे पास मौजूद है। जिनमें बार-बार कहा गया है, कि सप्लीमेंन्ट्री बजट क्यों मांगे जाते हैं, जब मांगा गया रूपया खर्च नहीं होता है और इसकी आवश्यकता नहीं है। बिना आवश्यकताओं का मूल्यांकन किए, क्यों प्रावधान किया जाता है। मैं आठवीं लोकसभा में पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की 147वीं रिपोर्ट, जो बहुत महत्वपूर्ण है, का उल्लेख करना चाहता हूं । वित्त मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को स्वीकार किया है और आदेश दिया है कि -

> "Any re-appropriation order issued during the year which has the effect of increasing Budget provision by more than 25 per cent or Rs.1 core whichever is more under a sub-head should be reported to Parliament along with the last batch of Supplementary Demands. In exceptional cases, any order or re-appropriation issued by the Ministries/Departments after presentation of the last Supplementary Demands should be with the prior approval of the Secretary/Additional Secretary, Department of Expenditure."

मंत्री जी, इस साल की ऑडिट रिपोर्ट मिली होगी। कितने उदाहरण हैं, जहां वित्त मंत्रालय के इस आदेश का पालन नहीं हुआ। एक्सपेंडीचर सैक्रेट्री तक की इजाज़त िवभाग ने लेना शुरु नहीं किया। इसका अर्थ क्या यह है कि वित्त मंत्रालय की पकड़ संसद की ओर से कमजोर पड़ रही है। मैं जानता हूं कि वित्त मंत्री जी कभी यह नहीं चाहेंगे कि उनकी पकड़ कमजोर हो, लेकिन क्या हालत है, क्या बात है कि जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वित्त मंत्रालय की पकड़ इस बार कमजोर पड़ रही है। मेरे पास सन् 1999, 2000 और 2001 की पब्लिक एकांऊटर कमेटी की रिपोर्ट विद्यमान है। सन् 1999 में -

> "In 15 cases relating to 15 grants as detailed below, although the supplementary provisions were obtained in anticipation of higher expenditure, the final expenditure was less than even the original grants. Thus the entire amount of supplementary provision aggregating to Rs.280.95 crore proved to be unnecessary. "

यानी इन्होंने जितना सप्लीमेंट्री बजट में पैसा मांगा, जैसे आज मांग रहे हैं। 280 करोड़ रुपए तब मांगा था, जब अंत में खर्चा देखा गया तो उन नई मांगो की आ वश्यकता ही नहीं थी। मैं उन ग्रांटों का नाम नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि सदन का समय लगेगा। ऐसे ही अननेसेसरी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के तमाम उदाहरण मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फूड, होम अफेयर्स, ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अलग-अलग प्रकाशित रूप में मौजूद हैं, जिनमें निरर्थक ग्रांट्स ली गईं। 68 केसों में उन्होंने सूचित किया कि हमने रिएप्रोप्रियेशन ज्यादा गलत कर दिया है।

> "In respect of remaining 96 cases, the exception was made the rule undermining the parliamentary financial control by different Ministries/Departments. In these cases, despite prior knowledge, the approval of Secretary (Expenditure) was obtained at the fag end of the financial year instead of reporting the re-appropriation to Parliament."

मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पार्लियामेंट को सूचना देने का काम भी संबधित विभाग न करे और वित्त मंत्रालय को स्वयं उसकी सूचना न हो तो ऐसे में कैसे वित्तीय नियंत्रण हो सकता है और कैसे विभाग धन का सदुपयोग कर सकते हैं।â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : तिवारी जी, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके दल का समय 38 मिनट है और आपको बोलते हुए लगभग 25 मिनट हो गए हैं। मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, अवगत करा रहा हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल) : अगर यह पहले बता दिया जाता तो मैं कम मेहनत करता।â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने आपको बोलने से रोका नहीं है, आप बोलिए। मैंने आपको केवल अवगत कराया है कि दूसरे माननीय सदस्यों के नाम भी हैं। आप इसे पूरा करिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं समग्र वित्तीय नियंत्रण, फिस्कल कंट्रोल की बात कर रहा हूं। जब मैं वित्तीय नियंत्रण की बात कर रहा हूं तो पूर्ण वित्तीय फिस्कल कंट्रोल की भी बात कर रहा हूं। अगस्त 2001 के मंथली रिव्यू इंडियन इकोनोमि में छपा है -

> "The fiscal discipline that was implemented on the expenditure of the Central Government during 2000-01 appears to be slipping as can be seen from the first quarter data for the fiscal year 2001-02. "

17.00 hrs.

जो तीन महीने के खर्च का विवरण आया है, According to the Controller General of Accounts, the Central Government expenditure during April- June, 2001 increased by 14 per cent as against a decline of 2.7 per cent during the corresponding period in 2000. पिछले साल मंत्री जी के आदेशों का पालन हुआ और 2.7 प्रतिशत खर्च घटा है लेकिन इस साल 3 महीनों में यह 14 प्रतिशत बढ़ गया है। वित्त मंत्री जी आप देखें कि यह क्या हो रहा है? The increase was more on account of non-Plan expenditure rather than for Plan expenditure. यह जो वृद्धि हुई, यह जो नियोजन के बाहर खर्च हुआ, साधारण खर्च हुआ, यह प्लॉन के लिए नहीं हुआ है। The non-Plan expenditure on interest payment, subsidy, defence payments, salaries etc. increased by 23 per cent during April - June 2001. The interest payments surged by 23 per cent as against a decline of 17.8 per cent during April – June, 2000. The Plan expenditure declined by 5.3 per cent during the first quarter of 2001-2002. ब्याज की पेमेंट के लिए हर वृद्धि जो पिछले तीन महीने में हुई, तो हमारा फिस्कल डैफेसिट कितना बढ़ेगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं।

The fall in the Plan capital expenditure was more than the decline in the Plan revenue expenditure. The Plan revenue expenditure fell by 4 per cent against an increase of 28 per cent during the same period of 2000. यह 2001-2002 में जो नियोजन का खर्च हुआ उसमें नियोजन संबंधी 5.3 प्रतिशत की कमी हुई। The fall in the Plan capital expenditure was more than the decline in the Plan revenue expenditure. The Plan revenue expenditure fell by 4 per cent against an increase of 28 per cent during the same period of 2000. जितने भी आंकड़े हमारे पास हैं ये इस बात की पुटि करते हैं कि वित्तीय नियंत्रण में और सख्ती की जरूरत है और दूसरी तरफ जो बुनियादी परिभाााएं हैं उनको बदलने की जरूरत है। इस वर्तमान वित्तीय वर्ा के पूरक बजट के जो प्रावधान हैं उनके बारे में अब मैं बताना चाहता हूं। इसमें कुछ प्रावधान हैं जो उचित हैं जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में होर्टिकल्चर के लिए, माइक्रो-मैनेजमेंट के लिए। लेकिन अगर इतना ही करना है तो जो नयी घोाणाएं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए की गयी हैं वे उसके मुताबिक नहीं हैं। ये मूल बजट की पूर्ति भी नहीं हैं जो नॉर्थ-ईस्ट के लिए होनी चाहिए। नेफेड के बारे में 100 करोड़ की पूंजी रखी गयी है लेकिन नेफेड जितनी खरीदारी करती है क्या यह उसके लिए पर्याप्त है? नेफेड ने कितनी मांग की है आप देखें? किसानों की स्थिति को देखते हुए आज यह आवश्यक है कि इस प्राइस-सपोर्ट को देखा जाए और नेफेड की क्या स्थिति है उसको देखा जाए। बजट में कोई टोटल ब्यौरा नहीं है। एक लाइन में दिया है, उसका कोई पूरा ब्यौरा नहीं है। पहले शासन में मैं देखता था कि पूरक बजट में भी मूल बजट की तरह पूरे खर्चे का ब्यौरा दिया जाता था। नॉर्थ-ईस्ट को कॉफी-बोर्ड, टी-बोर्ड, रबड़-बोर्ड और स्पाइसेज बोर्ड को केरल में और दूसरे कुछ राज्यों में कुछ सहायता दी गयी है, लेकिन यह भी बहुत कम है। यहां जो घोाणाएं की गयीं, यह उनके अनुरूप नहीं है और कॉफी-बोर्ड और रबड़-बोर्ड को सहायता उसके अनुसार नहीं है।

मुझे ऐसा लगता है कि आपको सैकिंड सप्लीमैंटरी लाना पड़ेगा। पब्लिक सैक्टर के लिए सरकार की जो नीति है, वह कमजोर है, अस्पट है कि यह भी इस पूरक बजट से साफ होता है। फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया, प्रोजैक्ट डैवलपमैंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कम्पनी के लिए कुछ रुपया रखा गया है। मैं जानना चाहूंगा कि जो फर्टिलाइजर कारखाने बंद हैं, उनके बारे में पिछले दिनों उर्वरक मंत्री जी ने घोाणा की है कि उन कारखानों को दोबारा खोलेंगे, ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर गठित किया गया है। गोरखपुर कारखाने के बारे में कहा गया है कि हम इसे पहले खोलेंगे लेकिन वह स्वीकृति कहां है। यह ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टरर्स मिलता क्यों नहीं है? फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कम्पनी के जो कारखाने बंद हैं उनके बारे में आपकी क्या नीति है? पब्लिक सैक्टर के आपने नौ रत्नों को बनाया। सब को मजबूरन पैसा नहीं देंगे तो उनका दम निकल जाएगा, वे फिर बीमार हो जाएंगे और डिसइनवैस्टमैंट के लिए जाएंगे। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री यह घोाित करें कि देश में पब्लिक सैक्टर जो बचा है उनके बारे में सरकार की क्या नीति है? आज क्या हो रहा है? जिन को पिछले साल पैसा दिया, सेल को पैसा दिया, एचएमटी को पैसा दिया, आज उनकी वित्तीय संस्थाएं वर्किंग कैपिटल के लिये मदद नहीं कर रही हैं। वित्तीय संस्थाए यह कहती हैं कि आपको सरकार से पैसा मिल गया, आपको संसद ने मदद दे दी , अब क्या जरूरत है। जब उन्हें वर्किंग कैपिटल नहीं मिलेगा,तो फिर हानि होने लगेगी । बैंकों का सारा पैसा मार्किट बॉरोइंग में ले लेंगे, आप खुद कर्ज लेंगे और उनको आदेश देंगे कि बाजार में जाओ, बाजार में कौन उनको रुपया देगा। मेरे पास वित्त मंत्री के आदेश हैं जिस में उन्होंने कहा है कि In July, 2001, the Minister asked all Public Sector undertakings to pursue their investment plan of utilising their reserves in addition to raising funds from the market.

बहरहाल इसी तरह आप देखें कि आईएफसीआई को दोबारा जीवित करने की बात हो रही है। अच्छा है, लेकिन उसके लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या है? इनको 400 करोड़ रुपए दिये जा रहे हैं। नाइजीरिया में एचएमटी की फैक्ट्री को दोबारा चालू कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है लेकिन ऐसे ही केनिया में और दूसरी जगह एचएमटी की मिलें हैं, वे भी पब्लिक सैक्टर की मिलें हैं। हमारे संबंध सबसे अच्छे कर रहे हैं। उन्हें फिर खोलने के बारे में सोचना चाहिए। वेज ऐंड मीन्स एडवांस टू स्टेटस के लिये 500 करोड़ रुपया रखा है। 500 करोड़ रुपए राज्यों को एडवांस देने के लिए रखे हैं। इसका क्या आधार है? जो नए राज्य बने हैं, आप उन्हें क्या सहायता दे रहे हैं? पुराने राज्य जिन की वित्तीय हालत खराब है उन्हें आप क्या सहायता दे रहे हैं? वेज ऐंड मीन्स एडवांस के केवल 500 करोड़ रुपए में क्या हो जाएगा? उत्तरांचल को स्पैशल दर्जा दिया है लेकिन उनको अतिरिक्त पैसा नहीं मिला। उत्तर प्रदेश की यह हालत है कि केन्द्रीय बिजली का भी बिल चुकाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। वहां बड़ा क्राइसिस है। केन्द्र सरकार ने उस संबंध में क्या किया है? पता नही।

मैं एक और अनुदान का स्वागत करता हूं। जर्नलिस्ट वैलफेयर फंड में एक करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह पत्रकारों के लिए है। यह किस तरह का फंड होगा, क्या होगा, किस से परामर्श किया गया? यह नहीं कहा गया कि यह किन पत्रकारों के लिए होगा ? सारी मीडिया जिस में केबल मीडिया भी शामिल है. के लिए होगा या राज्य के पत्रकारों के लिए भी है? यह स्पट नहीं है। इसमें कहा गया है केवल जर्नलिस्ट फंड एक करोड़ रुपए। खर्च पहले से एस्टिमेट होना चाहिए। फिशरीज के

लिए 3 करोड़ 88 लाख रुपए का प्रावधान था। यह पहले से बजट बनाते समय मालूम होना चाहिए। इसमें कई प्रावधान ऐसे हैं जिन का बजट बनाते समय ध्यान रखा जाना चाहिए था। बहरहाल मैं काफी समय ले चुका हूं। मैं इस बात का आदी नहीं हूं कि जो समय निर्धारित है उससे अधिक बोलूं इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। कहने को बहुत कुछ है लेकिन शायद फिर अवसर मिलेगा। यही कहूंगा कि कम से कम वित्त मंत्री जिन्हें प्रशासन का लंबा अनुभव है, वित्त के मामलों का पूरा अनुभव है वह यह देखेंगे कि नए परिपेक्ष्य में जबकि वैश्वीकरण के परिपेक्ष्य में बजटिंग पॉलिसी,, बजटिंग प्रोसिजर्स में क्या परिवर्तन करेंगे,

और उसमें सप्लीमेंटरी - जो पूरक बजट है उसका उपयोग किस तरह से करेंगे और बजट को परिमार्जित करने के लिए और उससे जो आज की वित्तीय आवश्यकताएं हैं, गरीबी को कम करने के लिए, बेरोज़गारी को कम करने के लिए, जो बंद कारखाने हैं, उनको दोबारा खोलने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जो डायनैमिक हों, प्रज्वलंत हों और समय की माँग के आधार पर एक नई दिशा देश को दे सकें, यही मेरा आग्रह और निवेदन होगा, माँग होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विरोधात्मक प्रस्ताव को एक रचनात्मक दृटिकोण से प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूँ।

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, I rise to support the Supplementary Demands for Grants presented by the hon. Finance Minister Shri Yashwant Sinha.

A very experienced hon. Member of this House, Chairman of the Public Accounts Committee, Shri Tiwariji raised a very pertinent point. The point he raised is - 'whether the new economy is beneficial for underdeveloped countries'. He concluded his speech referring to this. He made this point during the course of his speech also. My point is, in the present-day world, what else is the go? Once upon a time - when I did not know much about the economy - I was also caught in the tangle of *Swadeshi* and *Videshi*. Now, when we see the other countries in the world, especially the so-called Communist country like China queueing up before the WTO wanting to enter the comity of nations in the WTO; when we see the way they have progressed within the last ten years being also the same type of country like ours, having the same type of problems like us, having the same type of population like us; when we find that it has far surpassed us in economic stature, and is going to be the second biggest economy in the world, aspiring to be the biggest economy by 2020, what other road do we have to take except this road?

The new economy is an opportunity for India. The new economy is not against this country, it is an opportunity for this country. It has given us an opportunity to prove in the world that India can become a superpower. India can become a superpower by not giving protection to its industry. India can prove itself to be one of the best countries in the world, quality-wise also. Then only it is possible to become a superpower.

Though hon. Tiwariji has not mentioned about the economic slow down, I am very sure the other hon. Members who would rise to speak after me will positively mention the economic slow down. They would say that the economy is slowing down in India; in 1999-2000 the GDP growth was 6.3 per cent; and it has come down to 5.2 per cent in 2000-2001. They will definitely say that. They will also apprehend that it will go down further this year. But still, I will say that economic slow down is now a worldwide phenomenon.

Sir, not only these countries, even the United States of America, and Japan the second largest economy of the world are also passing through the similar phase. (*Interruptions*)

SHRI M.V.V.S. MURTHI (VISAKHAPATNAM): Our economic slow down is slower than that of other countries....(*Interruptions*)

SHRI KHARABELA SWAIN : Excepting China, there is no other country, even in Europe also, which is having 6 per cent average growth for the last five years. Take, for example, Japan, the second biggest economy of the world. Even their growth is not 6 per cent. Take, for example, Indonesia, Malaysia and Thailand. Just four to five years back, they were the Asian tigers. But now their GDP is not even 3.5 per cent.

But still here is our country, which, in spite of recession and Asia flue three years back, continued sustaining its development on an average of 6 per cent. Last year, due to bad monsoon and because of the slow down in agricultural economy, it went down to 0.2 per cent and attained the GDP of 5.2 per cent.

Now, with a very good monsoon predicted this year, we very much expect that there will be a turn around in September, and we will go even beyond 6.5 per cent GDP this year.

Sir, after coming to power, this Government has brought down the below poverty line percentage to 26. Previously, it was about 37 per cent....(*Interruptions*)

SHRI M.V.V.S. MURTHI : This figure of 26 per cent is not confirmed. The percentage of people below poverty line is much more than 26 per cent.

SHRI KHARABELA SWAIN : Anyway, I believe in the data given by the Government, and I take it as 26 per cent.

Sir, the foreign exchange reserves of our country is 43 billion dollars as against 750 million dollars in 1991. The industry is surviving in spite of import tariff falling from 135 per cent to 35 per cent over the last decade. In this span of time, the Government's investment is 28 per cent lower. That is the main reason for the slow down.

The slow down has been caused for the last five years because after the Fifth Pay Commission, so much of money was spent on salaries. So, the Government did not have much money for developmental work. Sir, 60 per cent of the entire revenue went on salary, emoluments and pensions of the Government employees. That is the basic reason for which the Government could not spend much. Because the Government could not spend much, there was an economic slow down.

Sir, the annual tax revenue this year is Rs. 2,01,000 crore. The repayment of principle amount for old loans is Rs. 2,85,000 crore. The amount of interest payment is Rs. 1,30,000 crore. It comes to a negative of Rs. 1,84,000 crore. With this negative amount, we have just started.

So, Sir, my point is that in spite of all these things, the Government is doing reasonably well, and it will also do well in future.

Sir, a point was raised by hon. Shri Narayan Datt Tiwari with regard to policy on public sector undertakings especially on disinvestment. I will not go into the very many details of it because just last week, we have had a detailed discussion in this very House which went on till 10 o'clock in the night.

It is being talked, time and again, about the revival package of the sick public sector units to revive them. In the last 10 years, Rs. 37,000 crores have been spent on the revival of different sick units. But not even a single unit could be revived. How do we just expect that if we again put money there, their condition will improve? What is the guarantee that their condition will improve after putting in money there on their revival?

Who can give guarantee? They say that jobs of the people will go. Jobs of how many people will go? Only 19 lakh people's jobs are involved. India does not belong to only 19 lakh people; India is having a population of 100 crore or 1,000 million. So, for the sake of only 19 lakh people, should 100 crore people suffer?

My point is that these should be disposed of as quickly as possible. We say that it is a crown jewel or that it is a family jewel. But hon. Minister Shri Arun Shourie was telling the other day that the conditions of so many public sector undertakings were so bad that no bidder was coming forward to buy them. So, they should be sold out as quickly as possible. When there are takers, at least, let us dispose them of because tomorrow may be too late. Let us not delay the process.

Hon. Finance Minister is present here. He knows that the Standard and Poor's, the international credit rating agency, has downgraded India's rating. What was the reason that they have for downgrading us? One of the major reasons was that the disinvestment process in India was very slow.

We are scaring away all the bidders due to the criticism in this House and also due to the agitation elsewhere. One of the hon. Chief Minister of one of the States in India has himself incited the strike and more than Rs.200 crore of BALCO was wasted in this way. He himself was the person who is now going for disinvestment of 29 State public sector undertakings.

The hon. Members from the Left Parties are always fighting. The hon. Members from the Left Parties are present here. I have with me, today's *The Hindustan Times.* I would just like to read out the heading. It says that "64 loss-making units to shut shop − CM." It is the CM of which State? He is the CM of West Bengal. I would like to quote what he said:

> "A technical committee set up to prepare a list of other sick undertakings have submitted its interim findings. We are going through them. PSUs must be financially self-sufficient. Otherwise, they have to close shop.
>
> Asked why he had criticised the Centre for its decision to wind up these undertakings when he himself was doing so, Bhattacharya said, they are targeting profit-making PSUs. We plan to close only the units that have been running on loss year after year."

That is what he said. Who will buy these loss-making units? Nobody will just come forward to buy them. Even now, nobody is coming forward. So, merely saying that dispose of the loss-making public sector undertakings − as if the buyers are queuing up − is not correct. The units that are profit-making today would be no more profit-making tomorrow.

MR. CHAIRMAN : Please wind up.

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, the first speaker spoke for nearly 35 minutes. I have taken only about 10 minutes. From the NDA, I am the first speaker; so, you may give me some more time, at least 5-10 minutes more. I know that I am a junior Member and I cannot compare myself with him. But kindly show me some sympathy and consideration.

My point is this. We have sold two units already − the Modern Food and the BALCO. They are success stories. The Modern Food has enhanced its production twice, after it has been privatised. It has also been able to increase the salaries of its employees by Rs.1,600 per worker. The workers are thus happy. So, I will appeal to the hon. Finance Minister that he should be strong enough in his attitude; he should not listen to any criticism; he should be very firm in disposing of those units because they are drain on national exchequer.

Another point is regarding the labour laws. Just two or three days bask we passed the Trade Union Bill. When we talk about the labour laws, a number of hon. Members feel that the workers should be protected. I do agree that the workers should be protected. I do not deny it. But my point is, we already have the Industrial Disputes Act, the Factories Act, the Minimum Wages Act, the Provident Fund Act, the ESI Act, the Bonus and Payment of Gratuity Act, etc. Are they not for protection of the labour? When we are having these many Acts, how many more do we require? In this country, the trade unions have become professional. They are anti-labour and they have become superfluous or rather counter-productive. They have become the main reason for closure of the industry. This perhaps is one of the reasons behind the foreign direct investment not coming to India. While China is getting about 47 billion dollars every year as foreign direct investment, we are getting hardly 3.8 billion.

I had been to China a month back. We met the hon. Prime Minister of China. We also met the trade union leaders. I asked a question to the hon. Prime Minister, "since you are allowing so much of foreign direct investment into China, do you not feel afraid that the foreigners will dominate the economy of China". The hon. Prime Minister said, "why should we be afraid of it. We are having a number of joint ventures and we are exporting 52% of total production out of these joint ventures". He also said that ten years back when any Chinese used to go to the United States of America he was coming back with goods made in USA but now any Chinese who is going to America is coming back with goods made in China. He has said that he is benefiting. China is allowing direct foreign investment even in the retail sector. The departmental stores, small shops are being run by the Taiwanese, Japanese, Germans and people from Hong Kong and USA.

In the infrastructure, agricultural and industrial sectors also, the foreign direct investment should be allowed. I would appeal to the hon. Finance Minister to put more emphasis on the infrastructure sector, particularly the housing sector.

We have seen that Chinese are now going in for the multi-storey buildings. Previously, it was said that China is a communist country and everybody there should live in a double-storey building. But now they are demolishing all the double-storey buildings and in their places constructing 50 to 70 storey buildings. When I asked the necessity of it, I was told, should they not provide the international standard of living to their people. He asked me, do I expect them to stay in the double-storey building for all the time. According to them, by constructing these big buildings, they are vibrating the economy. They say, it is not the responsibility of the Government to provide Government jobs to everybody but it is the responsibility of the Government to create an economic environment where everybody will be self-employed or will get a job on his own. That is the model which we should follow.

I would say that the foreign direct investment is not coming to India because of our bureaucratic procedure. It is so because of corruption or delay at the bureaucratic level. So, I would appeal to the hon. Finance Minister to look into the matter. China has also done the same thing.

They had identified 300 major industries all over the world just about ten years back. They invited them to start production in China and they gave them all the facilities. They provided the facility of reduced rates of tax to them and there was no bureaucratic hassle for them. There is no red tapism. That is why, the foreign direct investment is coming to China at such a high level.

1730 hrs (Dr. Raghuvansh Prasad Singh *in the* Chair)

Sir, in all the developed countries, the rate of power for the one unit is just Rs.2. In our country it is Rs.5. You will be surprised to know that in India the per unit cost of electricity for an industrial house is just two and a half times of the per unit cost for the residential house but in other countries, it is just the reverse. There the residential house owners have to pay just double than that of the industrial house. So, I would appeal that the Electricity Bill should be brought in this House and passed immediately.

As regards project implementation, we are lagging behind other countries. It should also be given a very serious thought.

Finally, with regard to infrastructure building, he has mentioned that Rs.2,500 crore has been given to the Pradhan Mantri Sadak Yojana. It is a Centrally-sponsored programme. I would appeal the hon. Minister to ensure that, at least, this project is properly implemented since it being an infrastructure building project. If you provide Rs.2,500 every year, I think the economy will become vibrant and there will be no economic slow down.

Lastly, I would like to make an appeal to the hon. Minister in regard to loans sanctioned to the States. In Orissa, 95 per cent of the revenue earned is spent on salary, allowances, and interest payment. So, I will appeal to the hon. Finance Minister that as the loan is too much, he should give a five-year moratorium on loan payment to Orissa so that after five years, Orissa does not come to the Central Government with a begging bowl.

सभापति महोदय : अब आधे घंटे की चर्चा ली जाएगी।

18.09 hrs.

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): Mr. Chairman, Sir, I am the only speaker from my Party. I may be given a little more time. Of course, I shall try to be as brief as possible.

Sir, I would like to avail of this opportunity to make a few observations about the overall economic situation in the country. As is well noted by all sections of this House, ruinous policies of this Government have started to take its toll. After ten years of economic reforms, there have been attempts to take stock of the progress or whatever you may call, the negative growth or failures by many organisations.

We can have a look at the mid-term appraisal, the RBI's report, the CMIE's report, the national survey of the National Council of Applied Economics and Research and all these things. In all the reports, one thing is comon, that is, there is sinking business, dipping investment, falling incomes and crashing stock market. The most strange spectacle is that the Government is totally clueless as to how to salvage the situation. One of the strange spectacles being noted is that the private sector people who were considered to be the main operators in the centre stage of economic reforms are requesting the Government to invest more. This is the strange sort of a spectacle.

While some speakers of the ruling side are waxing eloquence about the reforms, the Government, I believe, is seriously thinking of pump priming the economy. That is the Keynesian formula in such a situation. If that be the situation, the Government will have to go in for a large-scale investment, particularly, in the infrastructure sectors like road, power and all these things. If they have to do that, they have to throw to the winds the recommendations about fiscal deficit. On the one hand they are speaking about how sacred the Fiscal Responsibility Bill is and how it should be expedited, on the other hand they have no option but to respond to the call of the CII, FICCI and others that the Government should come in a big way and invest in the infrastructure sector. It may be in the road. There is already a National Highway project worth Rs.10,000 crore.

Regarding power, you know what has happened in Enron. Now, not only they have decided to withdraw but they are threatening that if you do not come to terms as they have proposed, more sanctions are waiting for you.

DR. NITISH SENGUPTA (CONTAI): They have denied that.

SHRI RUPCHAND PAL : Yes, they may have denied that but there was a threat and subsequently, it was diluted a little bit to re-strengthen, the sanction threat, on a subsequent date. But everywhere in the industrial sector, there is a slow down. The downward trend in the growth rate of industrial production continued in the second month of the first quarter. The growth was meagre 1.9 per cent. If you compare this with the last year, there is a steep decline, particularly, in the manufacturing sector markets, captial goods like steel, cement, and paper. Wherever you look at, it has come to such a pass. Last year, even after such a good off-take by the corporate sector from the banking system, it was only Rs.18,000 crore and the growth rate was 5.2 per cent. Now it has come down to Rs.1,900 crore or something. We can well imagine what is going to be the situation in the future. When the Prime Minister is always speaking about nine or 10 per cent growth, if this situation continues, even five per cent will be a matter of dream only. This will remain a dream. In such a situation, how does the Government propose to salvage the situation? Of course, one way is more investment by the Government. But how a judicious mixture it could be because we are already in a serious domestic debt.

We have already crossed the borrowing target by this time. It requires some creative imagination as to how best to do it without going further into the debt trap but still augmenting the Government investments, particularly in the infrastructure sector. Of course, in the social sector whatever maybe the claim about the decline in poverty situation, this is one way of calculation that can reach you to that level of 26 per cent from 36 per cent. You look at the exercise that has been done by an eminent economist. It says that this decline in poverty has not taken place at all; rather during the last ten years the gap between the rich and the poor has widened. If anyone has benefited, it is one section of the upper class who has been immensely benefited as a result of the liberalisation, privatisation and globalisation.

Someone was speaking about China. Every time we listen from the Government side, from the business houses, CII, etc. of taking MPs to China. We have a little bit of idea about China. You have been telling me that we are agents of China. ...(*Interruptions*)

DR. NITISH SENGUPTA : I doubt whether you know enough of China.

SHRI RUPCHAND PAL : Yes. We can claim it. We have been following it. As for me, I can tell you that from the age of 16, I am trying to follow it. ...(*Interruptions*) I am coming to that. They should know that in the case of China, it is the non-resident Chinese who are bringing the investments, a substantial part of it. In our case, it is only five per cent of NRI investments. Do you know that more than 110 billion dollars of Indian money is deposited in the tax havens in different parts of the world and in Swiss banks and other places? Our annual financial exercise is of 65 billion dollars and 110 billion dollars of Indian money is there.

DR. NITISH SENGUPTA : China does not have the bureaucracy. ...(*Interruptions*) It is not Indian bureaucracy. ...(*Interruptions*)

SHRI RUPCHAND PAL : You are speaking about it. We are not saying that you do whatever China has done. You should have your Indian model. How is it that the Swadeshi Jagran Manch says one thing and the BMS says one thing else and the Shiv Sena trade unions come to us and demonstrate against liberalisation and the reckless privatisation? Here they say another thing. We have noticed it. What happened in Maharashtra on the 23rd and 24th of July? The BMS unions, the Shiv Sena unions, the DMK and the AIADMK unions, every one of the trade unions was there. Can you find one single trade union which has been happy with the liberalisation process?

They are telling about the trade unions. Ten lakh people in the public sector have lost their jobs. They say that what a nice thing to be in the private sector! I am reading from a Government report. It is the IDBI's report on Development Banking in India. It is said : "As at end of March, 2000, private sector accounted for 82.6 per cent of total number of sick companies followed by public sector at 10.4 per cent and the joint sector at 7 per cent". Still they say that the public sector is not performing. I am again coming to this. It is not only about the number of sick companies. It is from the IDBI's report. They say that the creation of non-performing assets was the maximum in the private sector.

SHRI M.V.V.S. MURTHI (VISAKHAPATNAM): what is the diagnosis for it?

SHRI RUPCHAND PAL : I am coming to that. This is Government's report. The representative of the Government here is speaking in a different voice. In terms of the outstanding loans, the private sector accounted for the maximum. What is the maximum figure? It is 89.1 per cent. But still the villain of the piece is the public sector undertakings. China has not done it. China has a direction. China has knowledge of phasing, sequencing as to what is to be done and what is not to be done.

There, once a decision is taken, it is taken on consensus and they follow it and do it. We cannot do it.

SHRI M.V.V.S. MURTHI : China has closed more than a thousand units of chemicals.

SHRI RUPCHAND PAL : I will come to that. Please do not try to derail me from what I want to say. ...(*Interruptions*) Please do not try to derail me because this side or that side, they have committed the same sort of sin. As per the available report, it so happened once that the CII had taken a decision to recommendation clousre of the United Commercial Bank - a weak bank. The next morning the employees had come out with the list of defaulters saying, `Mr. so and so, you are sitting in the CII and taking the decision to close this Bank. Here is your name as you have not paid the money to the bank.' They had then withdrawn their decision.

Sir, many a time West Bengal is referred to. ...(*Interruptions*) At the end of March, Maharashtra accounted for the largest number of companies on the sick bed followed by Andhra Pradesh. ...(*Interruptions*) I am reading from the IDBI Report. Andhra Pradesh has 12.8 per cent such units. ...(*Interruptions*) Then comes Gujarat − and not West Bengal - where they have their own Government. ...(*Interruptions*) West Bengal's position is far below these states in this regard.

Not only industry, agriculture is also affected. It is the main driving force behind demand for industrial goods. You have to do anything to encourage export. But you cannot depend on export. Not only due to American slow down, near-recession or recession in Japan or all these things, but during the last 10 years, our export growth has not been noticeable. Moreover there is dumping. Liberalisation of imports has caused such a situation that agriculturists are suffering. They are not getting remunerative price. On the other hand, because of the stagnant situation and negative growth in agriculture, there is lesser and lesser demand of industrial goods and also the consumer goods.

The most horrifying thing is that our population growth is 1.8 per cent and the agricultural growth, particularly foodgrains, is 1.5 per cent. We are fast leading to a situation of famine because our yield is less. In China, agricultural yield is several times more than that of our country, be it foodgrains or anything like that.

Then, I come to IT sector. IT alone cannot do magic. IT is a tool which, if applied to agricultural sector, manufacturing sector and service sector, can expedite the growth. ...(*Interruptions*) It can do fine-tuning. Moreover, we do have very many bottlenecks in the infrastructure - telecom , power and many other areas. We cannot grow IT

out of nothing. We have been laying over-emphasis on IT. I do not say that IT should be ignored, but IT should be put in a more proper perspective. Hardware sector should be developed and also these IT coolies - this is someone else's expression - because IT is an area where the creativity will give you the result, not working for some other country or some other nation, going there, staying there, and earning money. In the case of non-resident Chinese, they are traders, but in our case, they are doctors, engineers, professionals etc.

SHRI M.V.V.S. MURTHI : Like that, India will also get some benefit. ...(*Interruptions*)

SHRI RUPCHAND PAL : I do not know why he is trying to add to my views.

Revenue collection is fast deteriorating. I am just giving a figure of the last quarter.

Sir, the tax collection in the first quarter of April to June has a shown a sharp decline of 13 per cent over the same period of last year. It was Rs. 32, 419 crore while the target was for Rs. 37,217 crore. This is particularly the case in regard to Customs and Excise duty. Another case in point is the consumption of diesel. The industrial situation in the country could somewhat be assessed from it. Diesel consumption has gone down by three and a half per cent. So, the situation is the same everywhere, be it with regard to agriculture, be it with regard to industry or be it with regard to the service sector.

Sir, let us now turn our attention to the financial institutions. The total NPA of the three financial institutions, namely, IDBI, IFCI and one other institution is more than Rs. 18,000 crore. I do not know as to what will happen to them. The RBI yesterday only had taken a very serious note in regard to provisioning of the balance sheets of the financial institutions. It is to the tune of Rs. 400 crore.

Sir, let us look at the core sector. I do not know as to what the Government proposes to do in the power sector. After what has happened with Enron, no foreign country, no foreign company is interested in the development of our infrastructure. Development of the infrastructure was a part of the 1944 Plan, known as the Tata Plan. It was suggested that certain areas should be identified where the Government should invest for its development because at that time the private sector was not in a position to do that. So, gradually, our first Prime Minister, late Pandit Nehru and others worked out a plan and identified certain areas that needed to be developed by the Government. Of course, there had been divisions in it. But I agree that hotels should not be an area where the Government should invest. I had been to Mongolia and I have noted there that very small and insignificant areas were taken up by the State sector as a result of which they had to suffer.

Sir, the Government should re-consider its reckless disinvestment policy. It is because there have been manipulations of the shares of the public sector undertakings. If there is a full-fledged discussion on the stock market − because disinvestment is discussed in a different light and in a different perspective − I can probably give enough proof to show that there have been manipulations in the share prices of some of the important public sector undertakings even before they were put for bidding. This has happened. Now, the Government proposes to bring it down. There are no bidders. The classic case in point is that of the Modern Foods Limited. The Government might not agree to it. The observation of the C&AG about Modern Foods Limited is about the process of its valuation.

Sir, let us take the case of BALCO. The employees of BALCO have submitted a memorandum to the CVC and the CVC has written to the employees seeking more documents. He said that he had gone through the documents and that there was a *prima facie* case and he has sought more proof on that. Now, there are profit-making undertakings. There are potentially good undertakings with large assets. I can give one example. Take the case of IISCO − Indian Iron and Steel Company. This organisation has more than 20,000 skilled workers. It is one of the oldest and one of the most prestigious institutions in the country. It has its own captive mine; it has its own good plant and it has its own good township. It is one of the best steel plants in the country. It has two units, one at Burnpur and the other is at Kulti and the Government had taken it over. Now, it is in the BIFR. The Government now proposes to release an amount of Rs. 500 crore, in two instalments, for this organisation. The first instalment is worth Rs. 150 crore. The amount of money that they have to pay on account of VRS to its employees is to the tune of Rs. 450 crore. We have written to both the hon. Prime Minister and the hon. Finance Minister. They have said that they are looking into the matter. So, this is about the public sector.

Sir, I would like to give an example in the private sector. Every time we have a discussion in the House, the Government says that with 26 per cent share, the Government would be able to have full control.

There the Government's stake can be brought down to 26 per cent. Okay. This is not the occasion to dispute it. There is a company in India called Dunlop India Limited in which the Government has a stake of 34 per cent. That company produced the best quality aero-tyres for the Indian Air Force. That company produced one of the best conveyor belts, a product which has a very good export market. It produced steel cord of international quality. Yet, the owner of the company siphoned off the money and went abroad. For fear of being arrested, he does not come to India at all. The Minister knows all these things. Several times we had approached the Defence Minister, the

Prime Minister and also the Finance Minister. We once again request him to apply his mind. Instead of going in for disinvestment in a big way to salvage the situation, he should go in for it very judiciously.

Not only Dunlop India Limited, there is the infrastructure sector, the national highway development programme. There is no problem because the banks are flush with money. They do not want to take risk of lending money. Moreover, there is less off take. I have spoken about power, I have spoken about infrastructure, I have spoken about IISCO, and I have spoken about Dunlop. In respect of ONGC, Mcinsey has already prepared a good report. As early as possible the Government should apply its mind to it. The Government should apply its mind to the problems of the people who have lost their jobs. By this time about one crore people have lost their jobs in different ways. The Government should seriously think as to how to provide employment to them in order to save them.

There are 75 public sector undertakings in BIFR. The dues on account of wages of employees as on 28th August, 2001, as given in the reply, are Rs.1,278 crore. Early arrangement should be made to make these payments. Ten years of economic reforms have led us into a blind alley. The Government finds itself in a clueless state. The Government should consult all the political parties. NDA meeting is going to take place on 1st September. The Government should hear the views and experiences of the NDA partners also on how best to go about it.

However, I do not think the Government is in a position to do that. They have a closed mind. Their partners are pulling in different directions. They are merely doing things without any philosophy or principle. They are indulging in corruption and they should go as early as possible.

Sir, I oppose the Supplementary Demands for Grants

.

DR. B.B. RAMAIAH (ELURU): Mr. Chairman, Sir, I would like to make a few points on the Supplementary Demands for Grants.

My first point relates to agriculture, the most important sector of the economy. More than 60 per cent of the country's population lives in the rural areas. In spite of the many difficulties that they have to face in their day-to-day lives, they work hard to be able to produce more foodgrains. Rice, wheat, sugar and so many other food items are in surplus now because of their effort. This is what is helping the country's economy stay under control now. On the industry side there is some recession. There is economic slow down because of that. Still, agriculture is really saving the country. We need to give more support for agricultural sector. I would like to make a mention of the natural calamities. I have suggested this earlier also. Cyclones and droughts are affecting the agricultural sector very badly. The Government should take initiatives to help these people to increase their capacity to produce. Exports are very important for a country's economy. We are trying to export our produce to different countries. A number of countries are doing exports because WTO does not prevent subsidy for exports.

In view of that, I believe that the hon. Finance Minister will take into consideration as to how to improve the agricultural side. It is very much required. During the last few months, we have had a very bitter problem. The Food Corporation of India is not able to procure these products and the farmers are unable to store their products with them. The warehouse is not adequate to store them. So, the farmers are forced to sell their products at very nominal prices due to which they suffer heavily.

My request is that if the Government can come out with some proposals for construction of warehouses and if there are some incentives for construction of warehouses, it will be of great help. If we are able to increase the capacity of the warehouses, more procurement may be made. But that is not the end of it. In addition, export of these things is also essential. Ultimately we will have to see that the surplus production should go out of the country and we will also have to keep enough amount of requirement for the country's resources.

Sir, in the Godavary basin, we had three times heavy floods during the last one month. About 70 per cent of the water is going to the sea whereas on the other side of the Krishna river, there is no water. Due to this, the whole agriculture had suffered badly. So, what I feel is that if we could take up the construction of Polavaram project, it will help the inter-connection of all these things. It will also help prevention of the flood damage and enable us maximum utilisation of water for agricultural purposes, for industrial purposes and for drinking purposes. For all purposes, water is very important. So, I think, this is one of the items on which the Government of India should take the initiative. The State Government which does not have enough resources, can become a partner here.

The hon. Finance Minister already knows about the State Government's difficult financial resources and economic position.

Sir, I may also mention that this year Andhra Pradesh has suffered a lot due to drought. More than 350 *mandals* had very little rains and about 500 *mandals* had meagre rains. The condition is very serious there. In this regard,

our State Government had already sent a proposal to the Government of India. A team of experts had also visited there. But in spite of all this, they have not been able to finalise the support that is required. In fact, our State Government has given a very detailed analyses with all the data and figures. We had asked that we needed Rs. 849 crore as support. They may not give the entire amount but they must, at least, release a substantial amount of support so that we are able to recover from our problems. For the water supply in the rural areas as well as urban areas, we have demanded Rs. 356. Similarly, for social security, animal husbandry, agricultural sector, we have asked for some help. Item by item, we have mentioned about the amount needed. I am sure that the Government will take all possible steps and timely help our State so that the people are able to recover from their problems and expand their activities.

Sir, another point which I want to cover is about the banking sector. We are talking about the banking systems and the various scams that have occurred there. We all know what happened in the case of UTI's US-64 scheme. We are also aware of the things happening in IDBI, IFCI and other such institutions. They are facing a lot of difficulties due to financial irregularities. So, they all require a proper control of the Government from the beginning.

In all the Banks and the financial institutions, the representatives of the Finance Ministry are there. They should watch the activities there. They should notice immediately as to where the things are going wong. If they do not observe all these things and if there are no such provisions, the situation will not improve. We all know what happened in the Harshad Mehta's Security Scam where the people had given a huge amount of money as loans without any security. That is why I suggest that it is part of the Government's responsibilities. The Finance Ministry should guide and instruct their representatives properly to take stern and proper action if any wrong is happening there. Otherwise, if everything goes out of their control, it will be very difficult.

Sir, today, they are thinking of providing Rs. 1,000 crore on revival of IFCI. Similarly, IDBI also needs more support. I am sure that the banking sector will be taken care of.

Sir, this has also happened in Andhra Pradesh. We know what happened in the case of *Krishak Urban Bank*. It was supposed to be under the control of the Reserve Bank of India. Earlier, we had seen the non-banking financial institutions where a tremendous amount of money had been invested by the people and they were exploited. They used to give a high rate of interest without anything. Then we thought of bringing them under the control of the RBI by putting the Non-Banking Financial Corporations (Regulations) Act .

Similarly, in regard to all these financial institutions and Banks, the RBI has to have control and have a minimum equity and all such things. All of them require proper scrutiny. Had all these measures been adopted and followed, these sorts of things would not have happened.

Today what is happening is that the savings of so many thousands of small investors worth about Rs.30-40 crore are lost. This is where the Government should help them. They should help them even by punishing those people who do mischief. I am sure the Reserve Bank of India has to give additional support, additional strength and additional control which they require. They should monitor these things. Otherwise, the financial institutions and others would make a lot of difficulties. The stock markets depend upon how these things are working. If stock market goes down, it has an impact. Earlier, some people were thinking that they have to invest only in gold. But now, we have developed the habit of bringing in industrial investment. Once it was discouraged, again they started going back to non-productive investments. We have to bring those people back to do industrial investments. The savings culture has come and the savings of small investors started growing. Suddenly, some difficulties are coming in and exposures are causing a lot of problems. I am sure there should be some regulation and the system should be improved.

Coming to industrial production, it has now slowed down. We have to find out the reasons for such a slow down; we have also to see how we can give more help to them. I believe that WTO, globalisation, etc. has nothing to do with that. For everything, there is a control; there is a mechanism by which we can control them. Some people have talked about how palm oil prices affected them. They have gone up to 300 per cent duty. We have to cautiously see our internal market. If you have heavy duty, there would be problems. The hon. Finance Minister also discussed it with us. Due to the increased duty, the prices have shot up and thus, the common man is affected.

We have leverage with us; the operation is controlled within our own country, and it is not that WTO is affecting us. Even some of these things require constant and frequent monitoring. We have got the mechanism of anti-dumping and the Anti-Dumping Department has started functioning now. It has got to be very active. Just like what is happening in the case of Foreign Investment Board, every week, they should review the decision and bring it to the notice of the Ministry; and they should take action as early as possible instead of taking a delayed decision. We have to take more interest on these items and this is what I feel.

Coming to the public sector undertakings, we have already invested about Rs.2,50,000 crore on it, but the return is very low; and even such a return is on account of administered prices. It is also due to oil sector and ONGC, etc.,

which are able to do something. But the losses are growing. There are three categories of industries. First is those industries which cannot survive and we have to close them down. For this, the hon. Minister has already brought in VRS, etc. It is really helping them. The second is those industries which can survive, but which need enough support. The third is those industries which are neither on this side nor on that side, which we can privatise. So, these are the three types of systems.

We are also reviewing some of these public sector undertakings. Initially we have given purchase preference for 2-3 years. But the other public sector undertakings are not trying to help them. We find that they are not at all supporting them, defeating the main purpose for which we have given purchase preference; and it is not properly utilised. Some very capable and quality industries are suffering because other public sector undertakings are not helping them. That is why we are trying to see how we can monitor these things. In this context, people are meeting Secretaries also and asking them what exactly is happening, what is the wrong with some of these units, like BHPV, etc. They will be able to produce quality goods than anybody else in the market, but still they say some how or other, they try to avoid them and give it to somebody else.

In the case of taxation, we have mentioned earlier that only 2-3 per cent of the people of this country is paying taxes. It is a broad-based one and we should cover more people in this country in the tax net. They may pay small amounts, but it will help. If taxes are heavy, then negative return starts. Instead of that, we have to distribute it widely and see that more people are brought into the tax net, by different methods. In fact, they started it in urban areas and increasing it in urban areas. It requires much more consideration. So, they have to see how taxation method can be improved. ...(*Interruptions*)

On the agricultural side, we have to help them with crop insurance. Some proposals are going on in this respect. Crop insurance schemes should come up as early as possible so that agriculturists who are really suffering are given support. There are places where crop insurance is not properly implemented. Of course they are having different methods by which they will be able to do it.

The most important sector is the infrastructure. Infrastructure is the basic thing we need today in the case of road, power and various other things. In the case of roads, we are now trying to get the road cess. By that we are able to build up something. A part of it, about Rs.2,500 crore, is used for rural roads. With regard to the Prime Minister Rural Sarak Scheme, we made a request. I have prepared a proposal and sent to the Government. The proposal is, at least Rs.2 crore should be reserved for each Member of Parliament exclusively for his recommendation. MPs have got a very little say in their areas. The hon. Finance Minister also knows about his own State. Every MLA is getting from Rs.75 lakh to Rs.1 crore. Several MLAs are equal to one MP. An MP is given only Rs.2 crore which was not properly utilised earlier but now we are utilising it properly. This year we have more than Rs.12 crore utilisation. We now have Supplementary Demands also. We would like the provision to be made to Rs.4 crore so that the MPs could also go to their constituencies and say that they also have some hand in the development of their constituencies. As part of the Sarak scheme, at least Rs.2 crore - for each MP area it comes to about Rs.5 crore − the Government should be able to reserve exclusively for MP's recommendation and the rest of it can be left for the MLA's recommendation so that MPs are also effective.

Old Age retirement benefit is one of the items which is pending and I am sure we will be able to pass it as early as possible. We should work out some mechanism on that and do something.

In the case of rural areas, rural development requires more support. In the Supplementary Demands we see very little is being provided on that score. Tourism is also an important area which requires support from the Government. We have not thought about it earlier. I am sure we should be able to give more help to it so that we get more benefit out of it. We will gain more foreign exchange out of this.

In the case of NAFED also, only Rs.100 crore has been given. It has to do a lot of purchase for these agricultural products. Along with the Food Corporation, they should come forward. For the export purposes, we need to give more support because export is one of the items which is able to save the country's economy. We need a good packing system also. Packing Institute in Hyderabad has offered something and the Government should give recognition and support to it. With their help, we would be able to gain.

One more item, which was started earlier, is called the brand equity. A number of good products are being manufactured by good companies but their products are not properly advertised outside. The brand name makes a lot of difference. I have seen in the case of a particular variety of pepper, when it was put in a known brand name bottle, it was sold at 3 dollars per bottle. People think that the particular brand is very good. So, I am sure the Finance Minister will be able to give more support to the brand equity, which was started earlier. A number of quality industries do not have enough resources to go to the brand name. If the Government gives them support, they will be able to come out of it.

Like that, we have to give support to aqua culture. It has started picking up. Last year we exported products worth

about Rs.6,000 crore. Fishermen from Vizag came here. They asked for the support of diesel so that a substantial amount of aqua culture could be developed. Some States have given help in the form of excise and customs duty. In other States also, where they have not, we should see that they should be given some help so that they will be able to develop aqua culture. This will bring a lot of resources for our country. A part of the items have been mentioned and a number of other items are required to be taken up by the Finance Minister in order to increase the economy and productivity.

Employment potential for youth is also an important item. Under DWAKRA Programme in Andhra Pradesh, ladies, who never used to come out, are doing a wonderful job. They need some support from the Government. A number of companies are coming forward to market their products. If the Government could give some support to them they would be able to convert tremendous amount of their energy into useful products. I am sure the Government will give a lot of support to these items.

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर) : सभापति महोदय, बड़े खेद का विाय है कि इस र्वा हमारे देश का बजट बिना किसी बहस के पारित हो गया। शायद इतिहास में यह पहला बजट रहा होगा कि जिस पर बहस नही हुई। दोा कहां रहा? लोग कहते हैं कि विपक्ष दोाी रहा। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार दोाी रही। अगर विपक्ष जेपीसी की मांग कर रही थी तो सरकार को उसका विरोध नहीं करना चाहिए था। इस कारण बिना बहस के बजट पारित हो गया। यदि बहस होती तो हम लोगों की तरफ से बहुत से सुझाव आते। हालांकि वह उसे मानें या न मानें यह अलग बात है। मैं वित्त मंत्री जी को अच्छे सुझाव देना चाहता हूं। वह उसे मानें या न मानें वह उनकी इच्छा है। देश को आजाद हुए 54 र्वा हो गए हैं। माननीय वित्त मंत्री गांवों में जाकर देखें। उन्होंने देखा भी होगा। शायद इस समय न देख पा रहे हों। गांव के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिला। आज भी उनके पास घर नहीं हैं। गांवों में सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तन ढ़कने के लिए कपड़ा नहीं है। उत्तर प्रदेश में लाखों लोग ऐसे हैं जो जाड़े में आग जला कर सर्दी से बचते हैं। इतना बड़ा बजट जाता है लेकिन वह गांवों में 10 परसैंट भी नहीं पहुंच रहा है। सारा पैसा ऊपर से लूट लिया जाता है। कांग्रेस की 40-45 र्वा तक हुकूमत रही। वित्त मंत्री जी का शायद यह चौथा बजट है लेकिन 40 बजट पेश करने वाले लोगों ने इस देश को कूड़े में फेंक दिया। कुछ भी गरीबों तक नहीं पहुंचा। वित्त मंत्री जी उनका अनुसरण कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं आया है। बोतल का केवल लेबल बदल गया है। जो कांग्रेस कर रही थी, वही बी.जे.पी. की सरकार कर रही है। आप जो ग्रांट देते हैं उसे चैक करें। राज्यों में जो योजनाएं चलती हैं उनका भी बुरा हाल है। आज समाजवादी पार्टी के लोगों को उत्तर प्रदेश में पीड़ा है, बिहार में भाजपा और दूसरे दल के लोगों को पीड़ा है, मध्य प्रदेश में दूसरे दल को पीड़ा है और राजस्थान में भाजपा को पीड़ा है। यहां से सीधे धन जिलो में जाता है। सांसदों को पता नहीं होता और न ही उनसे राय ली जाती है। एक सुनिश्चित रोजगार योजना है। इसके लिए भारत सरकार का पैसा सीधे ब्लॉक में जाता है। एक करोड़ रुपया यहां से गया। मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में काम देखा। वहां एक रुपए का काम नहीं हुआ। केवल एक नाले की सफाई हो गई। करोड़ों रुपए केवल कागज पर खर्च हो गए। अगर 10 लाख रुपए भी खर्चा होता है तो कहा जाता है कि बहुत खर्चा हो गया। आज गांव डूब रहे हैं, फसल डूब रही है। पैसा कागजों में जाता है। ग्रामीण विकास मंत्री को लिखते हैं तो वह सिचाई विभाग से रिपोर्ट मंगाते हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और चीफ इंजीनियर ने पैसा खाया होता है। वे गोलमोल करके रिपोर्ट दे देते हैं। वही चीज पहले हो रही थी और वही अब हो रही है। पैसे का सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है इसे देखें। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए पैसा गया। वहां इस पैसे से तनख्वाह बंट रही है। एम.एल.एज. से राय ली जाती है और लिस्ट मांगी जाती है लेकिन सांसदों से उत्तर प्रदेश में लिस्ट नहीं ली जा रही है। यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो उत्तर प्रदेश के अपने पार्टी के सांसदों को बुला कर पूछ लीजिए कि क्या सुनिश्चित रोजगार योजना में उनसे पूछ कर खर्चा किया जा रहा है? 1998 तक उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के सांसदों को निधि मिलती थी लेकिन वह बंद हो गई है। 1998 तक सांसदों से विद्युतीकरण के लिए पांच-पांच गांवों की लिस्ट ली जाती थी। उनसे एक-एक विधान सभा क्षेत्र में पांच की और पूरे संसदीय क्षेत्र में 25 की लिस्ट ली जाती थी

लेकिन बाद में सांसदों का नाम काट दिया गया है कि सांसद यह काम नहीं करेंगे, एम.एल.एज़ करेंगे। अगर भारत सरकार इलैक्ट्रिफिकेशन के लिये राज्य सरकारों को पैसा देती है, यह सदन सहमत होगा कि हममें से कोई विरोध नहीं करेगा। मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि सांसदो की राय ली जाये। यह हमारा अधिकार नही है कि हम गांव में एक खम्भा दे सकें, सुनिश्चित रोज़गार योजना में राय दे सकें और प्रधानमंत्री सड़क योजना में किसी सड़क के लिये नाम दे सकें। भारत सरकार की तरफ से एन.जी.ओज़ को विकलांगों के लिये पैसा दिया जाता है लेकिन उसका लाभ उन लोगों को नहीं मिलता। जो फर्जी संस्थायें हैं, सारा पैसा उनके घर पर पहुंच जाता है।

सभापति महोदय, सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत, मैं नहीं समझता कि मेरे संसदीय क्षेत्र में 100 लोग भी शिक्षा पा रहे होंगे। प्राइमरी स्कूल टूटे पड़े हैं। अगर सरकारी भवन बनाने के लिये पैसा दिया जाता है तो बच्चे पढ़ते नहीं और जहां पढ़ते हैं तो खुले आसमान के नीचे सर्दी, गर्मी और बरसात में लड़के-लड़कियां पड़े रहते हैं। इस बारे में कोई सोचता नहीं है।

सभापति महोदय, नाबार्ड या विश्व बैंक की सहायता से भारत सरकार सड़कें बनाने के लिये पैसा देती है लेकिन उत्तर प्रदेश में मेरे संसदीय क्षेत्र में जिस सड़क पर तीन परत मिट्टी पड़नी चाहिये थी, केवल एक परत ही मिट्टी पड़ रही है। यदि पैसे का सही उपयोग हो तभी दिया जाये और फिर हम अपनी जन-आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। मैं डेनमार्क गया था। वहां मैने देखा कि एक सड़क 1897 की बनी हुई थी लेकिन 100 साल बीतने के बाद भी उसकी मरम्मत के लिये एक पैसा खर्च नहीं किया गया है और वह सड़क वैसी की वैसी है। माननीय वित्त मंत्री जी, भ्रट अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं? मैं नहीं समझता कि माननीय वित्त मंत्री जी ने वित्त मंत्री के रूप में किसी अधिकारी के खिलाफ जांच कराई होगी। जब हम लोगों का वेतन बढ़ रहा है तो सारे देश में हंगामा हो रहा है। बड़े अधिकारियों, इंजीनियरों के लड़के-लडकियां विदेश में पढ़ रहे हैं, क्या आप उन लोगों का काला धन निकालने की कोशिश करेंगे? माफिया द्वारा लूट मचाई हुई है। उत्तर प्रदेश में बड़े लोगों के पास 100-100 करोड़ रुपया इकट्ठा हो चुका है, क्या सरकार उनका काला धन निकालेगी? क्या सरकार कोई नई चीज करके दिखायेगी? मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री ने कुछ नहीं किया है।

सभापति महोदय, आज चीन जैसे कई देशों से स्मगलिंग करके चोरी से माल यहां लाया जा रहा है और एक्साइज़ तथा कस्टम पर डाका डाला जा रहा है। वे कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं लेकिन चोरी से लाया गया सामान सस्ते दर पर यहां बेचा जा रहा है। इन सबसे सरकार को भारी घाटा हो रहा है। सरकार इन अनुपूरक मांगों द्वारा जो पैसा लेना चाहती है जिसका मैं विरोध करता हूं। मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इसे खोजने की कोशिश की है कि यह पैसा कहां जा रहा है। अगर पिछले पचास वार्ों में कोई सही काम किया गया होता तो हिन्दुस्तान इतनी तरक्की कर लेता। चीन इतनी तरक्की कर रहा है लेकिन हम लोग रोटी के लिये मर रहे हैं। अगर हमारी शिक्षा नीति सही होती तो जो पैसा एन.जी.ओज़ के माध्यम से दिया जा रहा है और बर्बाद हो रहा है, वह व्यर्थ नहीं गया होता। अगर हमारे बच्चे पढ़ लिए होते तो आज हमारी यह दुर्दशा न होती।

आज हमारी दो नीतियां चल रही हैं। अगर किसानों को कर्जा दिया जाता है तो वह पूरी तरह वसूल किया जाता है जबकि अमीर लोग कर्जा लेकर भी ठाठ से घूमते रहते हैं और देश को लूट रहे हैं। कर्जे से बचने के लिए वे कभी हाई कोर्ट से, कभी सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले रहे हैं। यदि किसान ने 10,000 रुपये कर्ज लिया है तो वह कर्जा धीरे-धीरे वापिस कर भी देता है। इस संदर्भ में मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र का एक उदाहरण देता हूं। ललन बिन्दू ने किसानी काम के लिए 10,000 रुपये का कर्जा लिया था जिसमें से उसने 8,000 रुपये का भुगतान कर भी दिया था। केवल 2,000 रुपये न देने पर उसे तहसीलकर्मी पकड़ कर ले गए और पीटते-पीटते उसे बुरी तरह मार डाला। जब किसानों ने आन्दोलन किया तो गोली चली। 2,000 रुपये कर्जा वापिस न करने पर उसे चौदह दिन के लिए बंद कर दिया गया जबकि अमीर आदमी मंत्री और अधिकारी से मिलता है और उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। यह दोहरा कानून किसलिए है? गरीब बंद किया जाता है जबकि अमीर कर्ज लेकर

भी देश को लूट रहा है। इस नीति में परिवर्तन होना चाहिए।

19.00 hrs.

उत्तर प्रदेश में 14 दिन हवालात में जिस ढंग से बंद किया जाता है, वहां चार-छः फीट की जगह होती है जिसमें खड़ा रहना पड़ता है। टट्टी-पेशाब भी वहीं करना पड़ता है। एक मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश में ऐसे हुए जो किसानों के नेता थे - मुलायम सिंह जी ने किसानों का 10000 रुपये का कर्जा माफ किया था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो किसान उत्तर प्रदेश में खुशहाल होगा और अमीर हवालात में बंद होगा। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी। हमने किसान पेन्शन लागू की लेकिन आज किसानों को पेन्शन नहीं मिल रही है। हमने इंदिरा आवास अनिवार्य रूप से देने की बात की। आज जो इंदिरा आवास उत्तर प्रदेश में चल रही है, वित्त मंत्री जी पता कर लें क्योंकि उसमें भारत सरकार से पैसा जा रहा है - जिसके पास दुमंजिला मकान हैं, जिसके पास स्कूटर है, कार है, जो माफिया हैं, वे इंदिरा आ वास का लाभ उठा रहे हैं और जो गरीब झोंपड़ी में रह रहा है उसके लिए इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं है। इन बातों पर वित्त मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। हम वित्त मंत्री जी को राय देंगे कि 10-15 सांसदों को बुला लीजिए कि उनके क्षेत्र में जो पैसा दे रहे हैं उसका उपयोग हो रहा है या नहीं, इसकी जानकारी कीजिए। मेरी समझ से आप एक बेरुखे टाइप के मंत्री हैं कि अधिकारी जो कहेंगे, वह करेंगे। अगर आप कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, देश में सुधार करना चाहते हैं, नई क्रांति लाना चाहते हैं, गरीबों तक रोटी पहुंचाना चाहते हैं, सड़कें पहुंचाना चाहते हैं, पानी पहुंचाना चाहते हैं, बिजली पहुंचाना चाहते हैं, तो करप्शन को रोकना पड़ेगा। अगर आप करप्शन को रोकने में सफल नहीं हैं तो इस देश के साथ बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है कि यहां की सरकार करप्शन को बढ़ावा दे रही है, करप्शन को रोक नहीं रही है। आपके समय में घोटाले हो रहे हैं, कांग्रेस के समय में घोटाले हुए। संयुक्त मोर्चा की सरकार रही तो अच्छी रही मगर इस सरकार से हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि यह गरीबों, किसानों और जो भुखमरे हैं, उनके लिए कोई योजना लाएगी। अगर आप में ज़रा भी दया हो तो ऐसी योजनाएं लाएं जिससे किसानों और गरीबों को लाभ हो।

मैं अंत में कहना चाहता हूं कि अगर आप यह कर रहे हैं तो आप सबसे पहले भ्रटाचार को रोकिये। जिस तरह से देश में भ्रटाचार बढ़ता चला जा रहा है, पनपता जा रहा है, आपकी सरकार में और भी भ्रटाचार बढ़ता जा रहा है। अगर वित्त मंत्री जी भ्रटाचार को रोकने में सफल हुए तो हमें विश्वास है कि हमारा देश तरक्की करेगा।

डॉ.लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, सरकार द्वारा अनुदानों की पूरक मांगें जो विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित हैं, उनका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ।

यह बात सही है कि पिछले समय से जब से एनडीए की सरकार है वित्तीय प्रबंधन के कारण काफी सुधार हुआ है। हमारी आर्थिक स्थिति सुधरी है, विदेशों में हमारे ऊपर विश्वास जमा है, एक ओर जहां हमारी प्रति व्यक्ति औसत आय में वृद्धि हुई है, वहीं विदेशी मुद्रा भंडार भी काफी अच्छा है। ऐसी स्थिति में हम विश्वास से कह सकते हैं कि हम आर्थिक स्थिति में निरंतर अग्रसर हैं, इसमें काफी प्रगति हुई है। हमने जो उपाय किये हैं, उनके कारण विभिन्न क्षेत्रों में जो अनावश्यक खर्चा था, उसमें कटौती हुई है और इसके कारण कई मंत्रालयों ने अपने से संबंधित जो स्टाफ है, उसमें भी कमी करने का निर्णय लिया है। उसके कारण भी अनावश्यक खर्चों पर प्रतिबंध लगेगा और उसके कारण जो बजट है, वह राट्रीय निर्माण की दृटि से, विकास की दृटि से सहायक होगा। मैं कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्ति करना चाहता हूं क्योंकि न तो मैं आर्थिक समीक्षा के उद्धरण देना चाहता हूं और न आंकड़े प्रस्तुत करके समय लेना चाहूंगा। कुछ बातें माननीय सदस्यों ने यहां पर कही हैं, उनको न दोहराते हुए संक्षेप में मैं अपनी बात रखूंगा।

सभापति महोदय, यहां पर नैफेड के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। यह सही है कि नैफेड का कार्य बड़ा विस्तृत है। देश में और बाहर भी उसे काफी काम करना पड़ता है, लेकिन पिछले समय से नैफेड के कार्यकरण में कुछ गिरावट आई है जिसके कारण चिन्ता स्वाभाविक है और यह आवश्यक है कि हम उसके कार्यकरण को ठीक करें। नैफेड के द्वारा किसानों को जो समर्थन मूल्य दिया जाता है, फिर चाहे वह सोयाबन का समर्थन मूल्य हो, गेहूं का समर्थन मूल्य हो या अन्यान्य किस्मों का समर्थन मूल्य हो, वह नैफेड के जरिए राज्य सरकारों को जाता है और राज्य सरकारें खरीद का प्रबन्ध करती हैं। कई स्थानों पर तो स्वतः केन्द्रीय सरकार अपने आप इस प्रकार का प्रबन्ध करती है, लेकिन पिछले समय में ऐसा देखने में आया कि केन्द्र सरकार ने जिन फसलों का समर्थन मूल्य घोति किया, उन समर्थन मूल्यों से नीचे जाकर किसानों को अपनी उपज बेचनी पड़ी और जो समर्थन मूल्य सरकार ने घोति किया था फिर चाहे वह नैफेड के द्वारा वहां तक पहुंचा हो, लेकिन राज्य सरकार द्वारा खरीद केन्द्रो का उस प्रकार का निर्णय नहीं लिए जाने से या सामयिक निर्णय नहीं होने से,समर्थन मूल्य प्राप्त नही हुआ। वह ठीक से नहीं पहुंचा और उसका लाभ किसानों को नहीं मिल सका।

सभापति महदोय, दूसरी बात यह है कि किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा जो वित्तीय सुविधाएं किसानों को मिलनी चाहिए वे नहीं मिल रही हैं। वित्त मंत्री जी यहां उपस्थित हैं मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्ति करना चाहता हूं। यहां पर फसल बीमा की चर्चा के साथ-साथ किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में भी चर्चा की गई है। अभी भी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जो व्यवस्था होनी चाहिए, जिन बैंकों को उन्हें उपलब्ध कराना चाहिए, किसानों को बैंकों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन बैंकों द्वारा उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। उन्हें कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब कहीं बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड मिलते हैं। जो पात्र किसान हैं उन्हें भी किसान क्रेडिट कार्ड समय पर नहीं मिल रहे हैं। इस बात को देखा जाना चाहिए।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ जैसा मैंने कहा कि फसल बीमा योजना का लाभ भी किसानों को ठीक प्रकार से नहीं मिल रहा है। फसल बीमा योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आती हैं, लेकिन मूलतः फसल के जो आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं, वे राज्य सरकार द्वारा ही उपलब्ध कराए जाते हैं कि किस फसल का कितना और किस प्रकार का नुकसान हुआ है। उसके बाद में केन्द्रीय सरकार अपनी तरफ से निधियां देती है, लेकिन राज्य सरकार से संबंधित जो निधियां हैं, जो निधियां राज्य सरकार की तरफ साधारण बीमा के लिए दी जानी चाहिए,या जो राज्य सरकार का अंशदान है, वह नहीं दिया जाता हैं। बीमा किश्त का किसानो से पैसा वसूल कर लिया जाता है, बैंकों में पैसा जमा है, केन्द्र सरकार का भी पैसा जमा है, लेकिन राज्य सरकार का अंशदान नहीं आने से किसानों को बीमे का जितना लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। मध्य प्रदेश में ऐसे कई उदाहरण हैं। माननीय वित्त मंत्री जी इस बारे में जानते हैं। मैं चाहूंगा कि फसल बीमा का पूरा-पूरा लाभ किसानों को मिल सके और हमारा जो साधारण बीमा निगम है, वह भी उसके अंदर गति लाए, ताकि फसल बीमा का काम ठीक प्रकार से हो सके।

सभापति महोदय, चूंकि अनुदान मांगों में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए निधि मांगी गई हैं, इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की ओर आकर्ति करना चाहता हूं। पिछले दिनों हमने देखा है कि विभिन्न राज्यों द्वारा कुछ योजनाएं प्रस्तुत की गईं। वे ठीक नही है। सांसदों की राय पहले नही मांगी । मुझे जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मध्य प्रदेश द्वारा इस योजना के अंदर एक ऐसी सड़क प्रस्तावित की गई, जो सड़क बनी हुई है और उसका आधा भाग डामरीकृत है। उस सड़क को फिर से बनाने के लिए 70 लाख रुपए फिर से खर्च करने का प्रावधान किया गया। मैंने उस पर आपत्ति उठाई कि सड़क बनी हुई है और यदि आधी सड़क बनाना चाहते हैं, तो बनाएं।â€¦ (व्यवधान) उसे फिर से देखा जाना चाहिये ।

कुंवर अखिलेश सिंह : सभापति महोदय, सदन के अंदर कोरम नहीं है। यह व्यवस्था का प्रश्न है।

महोदय, लेखानुदान मांगों पर चर्चा चल रही है और सदन में कोरम नहीं है, यह ठीक नहीं है। यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह सदन में कोरम की व्यवस्था करे। आप जिम्मेदार आदमी हैं। आप ऐसी बात मत कहिए।

सभापति महोदय, मैं कोरम का सवाल उठा रहा हूं। आप कृपया कोरम सुनिश्चित कीजिए। हम रोजाना यह देख रहे हैं कि छः बजे के बाद सदन चलता है और कोरम नहीं होता है। मेरा आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह है और मैं अपने प्रश्न पर बल दे रहा हूं।

सभापति महोदय : चूंकि अब आप बैठ गए हैं। इसलिए यह मान लेता हूं कि आप कोरम की बात पर प्रैस नहीं कर रहे हैं और आप मान गए हैं।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : सभापति महोदय, मैं नहीं माना हूं। मैं अपनी बात पर दृढ़ हूं।

सभापति महोदय : क्या आप कोरम प्रैस कर रहे हैं ?

कुंवर अखिलेश सिंह : जी हां, मैं कोरम प्रैस कर रहा हूं।

सभापति महोदय : ठीक है, बैल बजाई जाए।

19.11 hrs. बैल बज रही है -- **(Quorum bell is being rung)**

सभापति महोदय : सदन में कोरम का अभाव है, इसलिए सदन की कार्यवाही कल दिनांक 28 अगस्त, 2001 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

19.20 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on

Tuesday, August 28, 2001/Bhadra 6, 1923 (Saka).